Jan Swasthya Abhiyan

(Peoples Health Movement – India)

Health for All - Now! ***Health is a Basic Human Right!***

02 Feb 2023

विषय: केंद्रीय स्वास्थ्य बजट पर प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय सम्पादक महोदय,

कृपया संलग्न केंद्रीय स्वास्थ्य बजट पर प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त करें जो की जन स्वास्थ्य अभियान, जो जन स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्यअधिकारों के लिये कार्यरत कई जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच है, द्वारा तैयार की गयी है। आप से अनुरोध है कि इसे प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होने पर कृपया डॉ इन्द्रनील (9868701429); डॉ ऋचा (9910887838); डॉ रवि दुग्गल (9665071392); डॉ अभय शुक्ल(9422317515); डॉ सरोजिनी (9818664634) और अधोहस्ताक्षरी (9717107878) से संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद आपका

(वी आर रामन)
समन्वयक , जन स्वास्थ्य अभियान राष्ट्रीय सचिवालय

Addresses for Correspondence:
National Secretariat: K-65, Haus Khas Extension, New Delhi 110016.
Email: jsasect.delhi@gmail.com. Tel: 011-42576337
www.phmindia.org

केंद्रीय स्वास्थ्य बजट 2023-24 पर जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) प्रेस वक्तव्य

केंद्रीय स्वास्थ्य बजट में फिर गिरावट!

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और स्वास्थ्य अनुसंधान की उपेक्षा! कम उपयोग के बावजूद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) को बढ़ावा!

जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि "भारत एक चमकता सितारा बनकर उभरा है", "मजबूत व्यवहार्यता के संकेत दिखा रहा है", जबकि हम पाते हैं कि लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट आवंटन में और गिरावट आई है। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में भी बजटीय कटौती देखा गया है। पिछले साल के बजट में वास्तविक रूप से करीब 7 फीसदी की गिरावट देखी गई थी और इस साल के बजट में भी गिरावट आई है। 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में बजट 2023-24 में स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों के लिए वास्तविक रूप से आवंटन में 2% की कमी की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियान (JSA), जोकि आम अवाम का स्वास्थ्य नेटवर्क है, केंद्रीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए संबद्ध क्षेत्रों के अपर्याप्त बजट को सबसे मजबूत संभव शब्दों में निंदा करता है। यह देखते हुए कि लोगों ने COVID-19 महामारी के दौरान अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और कम संसाधन वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ बहुत कठिन अवधि का सामना किया था, JSA मांग करते आया कि जर्जर स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए ठोस उपाय किए जाएं और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए सही आवंटन किया जाए वर्त्तमान आवंटन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जाए। हालाँकि, सभी माँगें बहरे कानों पर पड़ी हैं।

स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों के लिए समग्र आवंटन में कटौती का विरोध करें!

यदि हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट (आयुष मंत्रालय सहित) को देखें, तो आवंटन 89,251 करोड़ रुपये (2022-23 बजट अनुमान) से बढ़ाकर 92803 करोड़ रुपये (2022-23 बजट अनुमान) कर दिया गया है, जो कि केवल 3552 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यदि हम मुद्रास्फीति के प्रभाव के लिए इसे समायोजित करते हैं तो वास्तविक रूप से इसका मतलब 2% की गिरावट है। **स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार का** व्यय **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में** देखें तो **2021-22** के **वास्तविक व्यय** और 20**23-24 बजट** आवंटन **के बीच 0.37% से घटकर 0.31% हो गया है ।कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2.26% से घटकर 2.06% हो गया है** - इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता कम कर दी है।

यह और भी चिंताजनक है कि पिछले बजट (BE 2022-23) में जो भी संसाधन आवंटित किए गए थे, उन्हें 2022-23 के संशोधित अनुमान (RE) में और घटा दिया गया है। **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन को INR 86200 करोड़ (2022-23 BE) से घटाकर INR 79145 करोड़ (2022-23 RE) कर दिया गया है - इसका मतलब है कि 8% की गिरावट।** हमें इस कटौती पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता

है क्योंकि यह आम लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इच्छा की कमी को दर्शाता है! केंद्र सरकार के RE के अनुसार स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.3% है और कुल केंद्रीय बजट का 2% से भी कम है। हमें इस तरह के गंभीर कटों का विरोध करने की आवश्यकता है और इसका संशोधन का मांग करने की!

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आवंटन में कटौती अस्वीकार्य!

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख योजनाओं में से एक **है**, जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है और माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए योगदान दे रही है। हालांकि, 2019-20 के बाद से एनएचएम आवंटन में वास्तविक रूप से गिरावट की जा रही है। **वर्ष 2022-23 में एनएचएम पर आवंटन रु. 37,159 करोड़ थी, लेकिन अब 2023-24 में NHM के लिए आवंटन केवल 36785 करोड़ रु है** जो न केवल 374 करोड़ की गिरावट है, **वास्तविक** तौर पर देखें तो **यह 1438 करोड़ रुपये की कटौती** माना जाना चाहिए। इसके अलावा, एनएचएम पर आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया जा रहा है या राज्यों को समय पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है- पिछले वर्ष की संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय में काफी गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि एनएचएम के तहत 2020-21 में जो अवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती रही, वे वर्तमान सीमित संसाधनों के साथ अब प्रदान करना आसान नहीं होगी। यह आवश्यक था कि सरकार सुरक्षित मातृत्व, सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास और महामारी के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का विस्तार करे, लेकिन इस प्रमुख आवश्यकता को बजट के अंतर्गत नजरअंदाज कर दिया गया है। NHM बजट के अंतर्गत शहरी स्वस्थ्य के लिए वास्तविक आवंटन भी कम होते दिखाई दे रहा है।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस आयुष्मान भारत- हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर की कुछ साल पहले इतनी धूमधाम से घोषणा की गई थी, वह बजट की रेखा से पूरी तरह से गायब हो गया है! 150,000 हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर बनाने की समय सीमा दिसंबर 2022 तक थी- लेकिन यह बिना किसी टिप्पणी के चली गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता थी, जिसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिख रहा है!

बेकार और अप्रभावी PMJAY को खत्म करें !

यह कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) कोविड-19 के दौरान गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही। इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान बीमा दावों में भारी गिरावट देखी गई। **बजट अनुमान 2021-22 में PMJAY के लिए आवंटित राशि 6400 करोड़ रुपये थी, लेकिन वास्तविक रूप में केवल 3115 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं !** भारी विफलताओं के बावजूद, सरकार इस बेकार योजना के लिए बड़े आवंटन को जारी रखे हुए 7200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि PMJAY के तहत 75% भुगतान निजी क्षेत्र को किया गया है, जो यह साबित करता है कि PMJAY जैसी योजनाएं सरकारी धन को निजी क्षेत्र में भेजती हैं। सरकार को तुरंत PMJAY

को खत्म कर देना चाहिए और इसके बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

हम यह भी नोट करते हैं कि CGHS योजना के तहत पेंशनरों के चिकित्सा उपचार के लिए बजट में 3846 करोड़ रुपये और शेष CGHS योजना के लिए 2200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये पर्याप्त वृद्धि हैं और इनमें से अधिकतर धन निजी प्रदाताओं के माध्यम से खर्च किए जाते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार बीमा पर जो कुल खर्च करती है वह अब 13,246 करोड़ रुपये है!

नौकरशाहों और सांसदों के लिए उच्च विशेषाधिकार को रोक दी जानी चाहिए!

नौकरशाह और संसद के सदस्य अपने स्वयं के विशेषाधिकार के लिए स्वास्थ्य बजट का एक बहुत मजबूत हिस्सा आश्वस्त करना जारी रखे हुए हैं। 42.38 लाख लाभार्थियों के लिए यह 6066.24 करोड़ रुपये है यानि कि प्रति लाभार्थी योगदान 14314 रुपये है और शेष केंद्रीय बजट 86737 करोड़ रुपये है (92803 करोड़ - 6066 करोड़ रुपये), जो प्रति आम आदमी 620 रुपये के बराबर है और यह माननीय नौकरशाहों और सांसदों पर खर्च किए जाने वाले खर्च का केवल छठा हिस्सा है। अगर हम राज्य के स्वास्थ्य बजट को जोड़ते हैं जो लगभग 340,000 करोड़ रुपये होता है तो भी प्रति व्यक्ति व्यय 2460 रुपये होता है!

पोषण, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवंटन पर उपेक्षा जारी!

जबकि एनएचएम आवंटन में कटौती सीधे प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को प्रभावित करती है, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं जो वर्तमान बजट के तहत उपेक्षित हो गए हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 **में सामर्थ्य योजना के लिए आवंटन में 41 करोड़ रुपये की गिरावट आई है जिसमें प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। आवंटन 2022-23 में 2622 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 2582 करोड़ रुपये हो गया है।**

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए आवंटन में केवल रुपये की मामूली वृद्धि हुई है। 291 करोड़। वर्त्तमान मूल्य में देखें तो इसका वास्तविक मतलब 4.3% की गिरावट है। इस योजना में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। हालांकि सरकार ने आईसीडीएस कार्यक्रम को फिर से ब्रांड बनाने की कोशिश की है, लेकिन आवंटन में व्यवस्थित रूप से कटौती की गई है। वास्तविक रूप में योजना के आईसीडीएस से संबंधित घटकों के लिए आवंटन 2014-15 में खर्च किए गए आवंटन से कम है। महिला सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना संबल योजना के लिए आवंटन 2023-24 के बजट में 562 करोड़ रुपये पर स्थिर है, और वास्तविक रूप से इसका मतलब गिरावट से है ।

बड़े-बड़े दावों के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य की लगातार हो रही उपेक्षा!

हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने पिछले बजट में एक विशेष राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की थी, मौजूदा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संस्थानों को बजट के अंतर्गत उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। **NMHP को मामूली रूप से 40 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है- जो 2019-20 से समान है। यह NMHP के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 30 पैसे खर्च करने के बराबर है!** इसके अलावा, ये आवंटित धनराशि भी काफी हद तक कम खर्च की जाती है; 2021-22 में वास्तविक व्यय था मात्र रु. 20.46 करोड़। जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पर्याप्त समर्थन और संसाधन के अभाव में टेलीमेंटल स्वास्थ्य पहल समाज के बेहतर तबकों तक ही सीमित रहती है। NMHP की स्थापना के कई वर्षों के बाद भी मानव संसाधनों में भारी अंतर बना हुआ है। केवल टेली-मेडिसिन कार्यक्रम पर भरोसा करके सेवाओं के प्रमुख अंतरालों को भरने की कोशिश का मतलब होगा कि समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रहेगा।

आवंटित बजट खर्च नहीं कर पा रहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, फिर भी आवंटन 70% बढ़ा!

पिछले वर्ष की तरह आवंटन में सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को प्राप्त हुआ है - पिछले वर्ष आवंटित 200 करोड़ रुपये से, एबीडीएम बजट 2023-24 के लिए बढ़कर 341 करोड़ रुपये हो गया है। भले ही पिछले साल आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने की संभावना नहीं है, इसमें एक वर्ष में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। एक महामारी के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार का आकर्षण, वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की उपेक्षा करते हुए, कार्यक्रम के मुख्य इरादों के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। **इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस योजना से बड़ी आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लाभ होने वाला है जबकि लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा और रक्षा संदिग्ध बनी हुई है।** इसके अलावा, निजी क्षेत्र की जानकारी के माध्यम से मरीजों को अधिक विकल्प प्रदान करने के सरकार के दावे के विपरीत, निजी संस्थाओं का पंजीकरण सफल नहीं हुआ और इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य ही विफल रहा!

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के बजट में कटौती!

हालिया कोविड संकट स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान पर दिए जा रहे ध्यान पर भी सवाल उठाता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए आवंटन स्वास्थ्य के कुल बजट का मात्र 3% है। वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य अनुसंधान पर वास्तविक व्यय स्वास्थ्य बजट का 3.8% था, जो वर्तमान बजट के आवंटन में घटकर 3.1% रह गया। इसके अलावा, **ICMR, जिसने टीकों सहित महामारी के दौरान कई शोध पहलों का नेतृत्व किया है,** का बजट आवंटन में **कटौती हुई है। 2021-22 के बजट में ICMR को 2358 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पिछले वर्ष (2022-23BE) आवंटन को घटाकर 2198 करोड़ रुपये कर दिया गया है - वास्तविक रूप से 17% की**

गिरावट। इस वर्ष आवंटन को बढ़ाकर 2359 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2021-22 के समान है। यही नहीं, इस पर वास्तविक व्यय भी केवल 1841 करोड़ रुपये पर बहुत कम है। यह कई स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की फंडिंग को प्रभावित करने वाला है जो ICMR फंडिंग पर निर्भर हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बजट ICMR के अनुसंधान प्रयोगशालाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलकर देने की बात कर रहा है, जिस से सरकार की नियत स्पष्ट है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के लिए बजट में तीव्र अस्पष्टीकृत कटौती!

पीएमएसएसवाई के लिए बजट में भारी कटौती की गई है, एक ऐसी योजना जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तर्ज पर तृतीय स्तर के अस्पताल और उच्चस्तरीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का निर्माण का एवं मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों / संस्थानों का उन्नयन का प्रावधान बनाया गया था। इस के लिए बजटीय आवंटन 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 3,365 करोड़ रुपये हो गया है।

जल, स्वच्छता और स्वच्छता बजट: वास्तविक रूप में गिरावट!

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने पिछले साल के बजट की तुलना में 7192 करोड़ रुपये बनाए रखा है- इसका मतलब वास्तविक तौर पर आवंटन में कटौती है। इसके अलावा, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों को घटाकर 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन को मिला दिया गया है और संयुक्त आवंटन में 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 700 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दी हुई है। जबकि अमृत में शहरी गरीबों के लिए एक फोकल सेगमेंट था, हमें यकीन नहीं है कि अगर इन योजनाओं को एक साथ देखा जाता है तो यह जारी रहेगा। कुल मिलाकर, जब परिणाम बजट की बारीकियों को देखा जाय, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र को मोदी सरकार की दो प्रमुख योजनाओं के होने के बावजूद वर्तमान केंद्रीय बजट के अंतर्गत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता नहीं दिया है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मा और वैक्सीन निर्माण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है! लोगों को दवाओं की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक वस्तुएं होने के कारण दवाओं को कम जीएसटी दरों के तहत रखा जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया! इस प्रकार केंद्रीय बजट बहुप्रतीक्षित राहत देने में विफल है!

अंत में, केंद्रीय स्वास्थ्य बजट 2023-24 बुरी तरीके से विफल होगी **क्योंकि इसने कोविड-19 महामारी के सबक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम व सेवाओं तथा महिलाओं और बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, और आवश्यक स्वास्थ्य अनुसंधान और बहुत महत्वपूर्ण संबद्ध क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक वृद्धि को आवंटित करने में विफल रहा। ऐसा लगता है कि इन बहुमुखी विफलताओं को ढंकने के लिए, वर्तमान स्वास्थ्य बजट में डेटा की प्रस्तुति को जानबूझकर अपारदर्शी और पिछले वर्षों की तुलना में कठिन बना दिया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियान इस देश के लोगों के साथ-साथ सभी सांसदों से इस विश्वासघात का विरोध करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, बहुत अधिक आवंटन की मांग करने का आह्वान करता है, जो हम सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।